(ग) विगत वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार ऐसे कितने गोदाम स्थापित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) और (ख) कृषि स्तर पर वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1979-80 से ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों की स्थापना के लिए एक योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:- कटाई के तुरन्त बाद खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की घाटे की बिक्री को रोकना, घटिया किस्म के भण्डारण की वजह से मात्रा और गुणवत्ता में होने वाली हानियों को कम करना और कटाई के तत्काल बाद की अवधि में बाजार भण्डारण सुविधाओं और परिवहन पर पड़ने वाले दबाव को कम करना तथा किसानों को कृषि में काम आने वाले कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करना। केन्द्र सरकार इन गोदामों के निर्माण हेतु सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 1993-94 की केन्द्रीय वार्षिक योजना से इस योजना को हटा दिया है और अब यह राज्यों की वार्षिक योजना का हिस्सा होगी।

(ग) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे गोदामों की स्वीकृति नहीं दी गई थी। तथापि, इस योजना के प्रारम्भ होने के बाद 528 गोदामों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार 528 गोदामों में से 425 गोदामों का निर्माण किया जा चुका है और बाकी गोदामों के निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में है।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेय जल मिशन

2796. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पेयजल मिशन स्कीम शुरु की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इस मिशन के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसकी जिला-वार वास्तविक रूप से कितनी प्राप्ति हुई;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इन गांवों को शामिल करने के लिए पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आबंटित/प्रदान की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल): (क) जी हां। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत आगरा, मिर्जापुर, सुलतानपुर और उन्नाव के मिनी-मिशन जिलों में पेयजल सप्लाई योजनाएं शुरु की गई हैं, फ्लोराइड कम करने, पानी से लौह को दूर करने के संयंत्र लगाए गए हैं और जल एकत्रीकरण ढांचों का निर्माण किया गया था।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त-उपलब्धियों के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिये लक्ष्य वार्षिक योजना परिव्ययों में वर्ष दर वर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य सभी ग्रामीण बस्तियों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना है।

(घ) 1991-92 में उत्तर प्रदेश सरकार को रिलीज की गई निधियों और उनके प्रयोजनों को विवरण - 2 में दर्शाया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां

	योजना का नाम	कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	गत 3 वर्षों के दौरान कवर किए गए गांवों की संख्या
1.	मिनी मिशन		
	आगरा	77	33
	मिर्जापुर	1245	1245
	सुलतानपुर	193	148
	उन्नाव	35	35
2.	उप-मिशन	अनुमोदित संयंत्रों की संख्या	अभी तक शुरु किए गए संयंत्रों की संख्या

	फ्लोराइड दूर करने के संयंत्र	12	12
	लौह दूर करने के संयंत्र	276	276×
3.	जल एकत्रीकरणरिलीज की गईअब तक खर्च ढांचे राशि की गई राशि (करोड़ रुपये में)		
	आगरा	0.19	0.01
	हमीरपुर	0.81	0.53
	मिर्जापुर	1.41	असूचित
	सुलतानपुर	2.24	2.21

× 17 अतिरिक्त संयंत्र लगाए गए हैं।

विवरण-2

उत्तर प्रदेश सरकार को रिलीज की गई निधियां और प्रयोजन

क्रमांक	मद	राशि	प्रयोजन
		(करोड़ रुपये में)	
1.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	47.24	पर्वतीय तथा समतल क्षेत्रों के बिना जल स्रोत वाले और आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों की कवरेज
2.	अम्बेदकर शताब्दी कार्यक्रम	6.70	अनुसूचित जाति/जनजाति बस्तियों की कवरेज के लिये
3.	बिना जल स्रोत वाली श्रेणी के गांवों के लिये विशेष सहायता	28.67	बिना जल स्रोत वाले समस्याग्रस्त गांवों की कवरेज के लिये
4.	विशेष सहायता	8.54	गत वर्षों में किए गए अधिक खर्च को कवर करने के लिये
5.	मिनी मिशन	0.366	आगरा, मिर्जापुर, सुलतानपुर और उन्नाव के 4 मिनी मिशन जिलों में अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्माण-कार्य करने के लिये।

उत्तर प्रदेश में कुओं की खुदाई में खर्च की गई धनराशि

2797. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित धनराशि का 20 प्रतिशत का इस्तेमाल कुओं की खुदाई के लिये किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या यह भी सच है कि इस स्कीम के अन्तर्गत किए गए कार्य का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और विगत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में जिला-वार कितने कुएं खोदे गए तथा जवाहर रोजगार योजना कोष में से इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी): (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शामिल है, में 20 प्रतिशत निधियां दस लाख कुंओ की योजना के लिए निर्धारित की गई है जिसके अन्तर्गत खुले सिंचाई कुंए, तालाब, जल एकत्रीकरण ढांचों आदि जैसी लघु सिंचाई योजनाएं चलाई जाती हैं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों की भूमि का विकास भी किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) दस लाख कुओं की योजना जो कि जवाहर रोजगार योजना की एक उपयोजना है, के अन्तर्गत खोदे गए कुंओं की जिलावार संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इस दस लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत खोदे गए कुंओं की संख्या और उन पर खर्च की गई राशि नीचे दर्शायी गई है:—

वर्ष	खोदे गए कुओं की संख्या	किया गया खर्च (लाख रु० में)
1990-91	2777	3767.97
1991-92	8780	12541.02